संसद में आकर जवाब दे सरकार

संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर साधा निशाना

नई दिल्ली, 05 अगस्त. संसद के मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी राजनीतिक खींचतान के बीच विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है.

खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार के शीर्ष नेता महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के दौरान सदन से दूरी बनाए हुए हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से संसद में उपस्थित होकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने की मांग की.

खड़गे ने खास तौर पर दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया. उन्होंने छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सरकार से जवाब मांगा.

विपक्ष का कहना है कि छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए और सरकार को पुलिस कार्रवाई से संबंधित परिस्थितियों को स्पष्ट करना चाहिए. खड़गे ने श्रीराम मंदिर से जुड़े दान और चंदे में कथित गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने इस संबंध में सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. विपक्ष के नेता ने कहा कि संसद में जनता और देश से जुड़े गंभीर विषयों पर चर्चा होना जरूरी है

छात्रों से जबरन माफीनामा लिया गया : राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्रों और युवाओं के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि देश के छात्र अपनी मेहनत, अधिकार और भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में उनका लगातार शोषण किया जा रहा है. राहुल गांधी ने विशेष रूप से परीक्षा प्रश्नपत्र लीक, परीक्षाओं के रद्द होने और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. राहुल गांधी ने कहा कि देश के लाखों छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्षों मेहनत करते हैं. ऐसे में जब प्रश्नपत्र लीक होने या अन्य कारणों से परीक्षा रद्द होती है तो इसका सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ता है. उन्होंने कहा कि छात्रों की मेहनत और उनके सपनों को इस तरह बर्बाद नहीं किया जा सकता. राहुल गांधी ने मांग की कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके. प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया. उन्होंने जंतर-मंतर और अन्य स्थानों पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ हुई कथित पुलिस कार्रवाई की सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की.

20 मिनट में 7 धमाकों से धुआं-धुआं दुबई

नई दिल्ली, 05 अगस्त. एक तरफ ओमान और ईरान की वार्ता चल रही है कि खाड़ी में हालात सामान्य हो जाएंगे. होर्मुज पर सेटलमेंट की बात के बीच संयुक्त अरब अमीरात का दुबई शहर फिर निशाने पर आ गया. यहां बुधवार को सुबह-सुबह हड़कंप मच गया, जब जाबेल अली इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार कई जोरदार

▸ यूएई में ईरान के गुर्गों की करतूत

धमाके हुए. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में आसमान में धुएं के बड़े-बड़े गुबार उठते दिखाई दिए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर के मुताबिक अमीराती अधिकारियों ने दावा किया कि करीब 20 मिनट के भीतर कम से कम 7 धमाके हुए.

हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि इन विस्फोटों की वजह क्या थी न ही इसका अभी तक आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है. धमाके जाबेल अली पोर्ट और उसके आसपास के औद्योगिक क्षेत्र में हुए, जो यूएई का एक महत्वपूर्ण पोर्ट और फ्यूल डिस्ट्रिब्यूशन का सेंटर माना जाता है. इसके अलावा इसे लॉजिस्टिक्स हब भी कहा जाता है. गनीमत ये है कि अब तक किसी के जख्मी होने या बड़े नुकसान की खबरें नहीं आई हैं.

> घटना के बाद सोशल मीडिया पर धमाकों और आग के वीडियो तेजी से वायरल होने लगे. अमीराती अधिकारियों ने घटना का वीडियो बनाने वाले दो लोगों को हिरासत में लिया है. मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि ये धमाके यमन से दागी गई मिसाइलों की वजह से हुए. वहीं अमीरात के स्थानीय मीडिया ने केवल इतना कहा कि कई धमाकों की आवाजें सुनी गईं, लेकिन मिसाइल हमले या किसी अन्य कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की.

मुंबई पुलिस में बड़ा वेतन घोटाला

मुंबई, 05 अगस्त. मुंबई पुलिस विभाग में सामने आए कथित वेतन घोटाले ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ विभाग की आंतरिक निगरानी प्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

फर्जी नामों से निकले 6.5 करोड़

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2019 और 2020 के दौरान 10 ऐसे लोगों के नाम पर करीब 6.50 करोड़ रुपये की तनख्वाह निकाली गई, जो कथित तौर पर मुंबई पुलिस के कर्मचारी थे ही नहीं. इन लोगों ने बिना वर्दी और बिना पुलिस की नौकरी के करीब करोड़ों रुपये का वेतन हासिल किया.

> मामला करीब छह साल पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इसके सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है. जिन 10 लोगों के नाम से वेतन जारी किया गया, उनका मुंबई पुलिस के वास्तविक कर्मचारियों के रिकॉर्ड में कोई अस्तित्व नहीं था. इसके बावजूद वेतन भुगतान की प्रक्रिया चलती रही और कथित तौर पर करीब साढ़े छह करोड़ रुपये की राशि उनके नाम पर जारी हो गई. इस पूरे मामले ने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा किया है कि आखिर बिना नियुक्ति के किसी व्यक्ति का नाम पुलिस विभाग के वेतन रिकॉर्ड तक कैसे पहुंचा. इतना ही नहीं, यदि इन लोगों को नियमित तौर पर वेतन दिया जा रहा था तो विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की उपस्थिति, नियुक्ति रिकॉर्ड और वेतन

फिर कह रहा हूं कि कोई गोली नहीं चली : पात्रा

राहुल के आरोपों पर संबित पात्रा का पलटवार

नई दिल्ली, 05 अगस्त। राहुल गांधी की प्रेसवार्ता के कुछ ही समय बाद भाजपा ने उनके आरोपों का जवाब दिया. भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि 20 तारीख को हुए संसद चलो मार्च के दौरान कोई गोली नहीं चली थी.

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी भाजपा ने यही बात कही थी और अब भी पूरी जिम्मेदारी के साथ वही दोहरा रही है. पात्रा ने राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया. राहुल गांधी ने प्रेसवार्ता में छात्र प्रदर्शन में

शामिल युवाओं के साथ मंच साझा किया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रदर्शन के बाद छात्रों को धमकाया जा रहा है और उनके घरों पर दबाव बनाया जा रहा है. इसके जवाब में संबित पात्रा ने कहा कि उनकी प्रेसवार्ता छात्रों के खिलाफ नहीं, बल्कि राहुल गांधी के बयानों के जवाब

कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन को मिला एक साल का विस्तार

नई दिल्ली. सरकार ने कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन और गृह सचिव गोविंद मोहन को एक-एक साल का सेवा विस्तार दिया है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किये. श्री मोहन 23 अगस्त 2024 से गृह सचिव के पद पर हैं. इससे पहले वह संस्कृति मंत्रालय में सचिव, गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और आर्थिक मामले विभाग में संयुक्त सचिव समेत केंद्र और सिक्किम सरकार के विभिन्न विभागों में कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं. श्री मोहन के पास भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद से प्रबंधन में डिप्लोमा की डिग्री है.

राजनाथ सिंह से मिले हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा

नई दिल्ली, 05 अगस्त. हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने बुधवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास पर शिष्टाचार भेंट की. इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने, राज्य के विकास, सुशासन और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ. महिपाल ढांडा ने केंद्रीय रक्षा मंत्री को हरियाणा सरकार की ओर से शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों की जानकारी दी. उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य में प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की. शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया जा रहा है.

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
"मिनी रत्न कम्पनी"
(कोल इंडिया लिमिटेड का उपक्रम)

सूचना

एसईसीएल द्वारा सामग्रियों, कार्यों एवं सेवाओं की खरीद के लिए जारी निविदाऐं एसईसीएल की वेबसाईट http://www.secl-cil.in, कोल इंण्डिया के ई-प्रोक्यूमेंट पोर्टल http://coalindiatenders.nic.in और सेन्ट्रल पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल http://eprocure.gov.in पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जीईएम पोर्टल http://gem.gov.in के माध्यम से भी खरीदी का कार्य किया जाता है। एसईसीएल के माईनिंग सर्विसेस की निविदायें भी अब जीईएम पोर्टल http://gem.gov.in पर उपलब्ध हैं।

मांग नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3(1) के अंतर्गत। उक्त नियमों के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (IIFL HFL) (जिसे पहले इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ता(ओं) से उन्हें जारी किए गए संबंधित डिमांड नोटिस(ओं) में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया है। उपरोक्त के संबंध में, उधारकर्ता(ओं) को इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान डिमांड नोटिस की तिथि(ओं) से भुगतान की तिथि तक के अतिरिक्त ब्याज सहित करने के लिए सूचित किया जाता है। ऋणी(ओं) का विवरण, मांग नोटिस की तिथि तक देय राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए दी गई सुरक्षा निम्नानुसार है:-

ऋणकर्ता/ गारंटर का नाम	मांग नोटिस दिनांक और राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
श्रीमती सपना सेन रवि ट्रेलर्स श्री रविशंकर सेन, सपना सेन (प्रोस्पेक्ट नं. IL10628609)	08-जुलाई-2026, रू. 17,69,745/- (सत्रह लाख उनहत्तर हजार सात सौ पैंतालीस मात्र)	संपत्ति का पूरा विवरण इस प्रकार है: प्लॉट नं. 26, पीएच नं. 77, Div ख. नं.132, ख. नं. 132/1/1/1, वार्ड नं. 72, मौजा कचनारी, RNM मधोताल, तहसील मधोताल, जिला जबलपुर, म.प्र., 482002। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: जमीन का क्षेत्रफल, बिल्ट-अप एरिया, कारपेट एरिया। संपत्ति का क्षेत्रफल: 800.00, 800.00, 720.00।

अगर बताए गए उधारकर्ता IIFL HFL को ऊपर बताए अनुसार पेमेंट नहीं करते हैं, तो IIFL HFL ऊपर बताई गई सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ उस एक्ट की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत कार्रवाई कर सकता है। यह पूरी तरह से उधारकर्ताओं के जोखिम, खर्च और नतीजों पर होगा। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें: ब्रांच ऑफिस: 225, नेपियर टाउन, दूसरी मंज़िल, चंद्रिका टावर्स के सामने, शास्त्री ब्रिज रोड, जबलपुर - 482001। कॉर्पोरेट ऑफिस: IIFL टावर, प्लॉट नंबर 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गांव, हरियाणा।

स्थान: जबलपुर
दिनांक: 06.08.2026
एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए

▸ एक नजर में ◂

रांची में छात्रों के आंदोलन का 12वां दिन

रांची. झारखंड में जेएसपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित धांधली और प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ चल रहा छात्रों का आंदोलन बुधवार को 12वें दिन में प्रवेश कर गया. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बड़ी संख्या में छात्र अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं. लगातार चल रहे प्रदर्शन के बीच बुधवार को प्रशासन और मुख्यमंत्री आवास की ओर से आंदोलन स्थल पर अधिकारियों के पहुंचने के बाद मामले में बातचीत की उम्मीद जगी है. रांची सदर के अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत और अपर जिला दंडाधिकारी धनंजय कुमार छात्रों के बीच पहुंचे. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संदेश का हवाला देते हुए आंदोलनकारी छात्रों से पांच प्रतिनिधियों का चयन करने को कहा. इन प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री आवास ले जाकर सीधे मुख्यमंत्री से बातचीत कराने का प्रस्ताव रखा गया है. प्रशासन की इस पहल के बाद छात्रों ने तुरंत प्रतिनिधिमंडल के नाम देने से इनकार नहीं किया, लेकिन फैसला लेने के लिए समय मांगा.

नए सिरे से दिशा केस की जांच हो

मुंबई, 05 अगस्त। दिशा सालियान की मौत से जुड़ा मामला एक बार फिर कानूनी चर्चा के केंद्र में आ गया है. दिशा के पिता सतीश सालियान ने अपनी बेटी की मौत को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए मामले की नए सिरे से जांच की मांग की है. उन्होंने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच कराने और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है. पिता का दावा है कि उनकी बेटी के साथ अनहोनी हुई थी और इस संबंध में उनके पास अदालत के सामने पेश करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं. सतीश सालियान ने शुरुआत से ही मुंबई पुलिस की उस थ्योरी पर सवाल उठाए हैं, जिसमें दिशा की मौत को आत्महत्या बताया गया था. उनका कहना है कि बेटी के शरीर पर ऐसे चोटों के निशान नहीं थे, जो ऊंचाई से गिरने के कारण होने चाहिए थे. इसी आधार पर उन्होंने मामले की जांच पर सवाल उठाते हुए इसे दोबारा देखने की मांग की है. मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है. अदालत ने मुंबई पुलिस से सवाल किया है कि जब दिशा के पिता ने हत्या का संदेह जताते हुए शिकायत की थी, तो उस शिकायत के आधार पर प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई.

हस्तियों के ट्वीट

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि 'मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ कि जब अनुच्छेद 370 को हटाने वाला ऐतिहासिक बिल पास हुआ, तब मैं संसद का सदस्य था. साथ ही, यह मेरा सौभाग्य था कि मुझे 5 अगस्त को राज्यसभा में और फिर 6 अगस्त, 2019 को लोकसभा में बोलने का मौका मिला.

पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और गृहमंत्री अमित शाह के अटूट संकल्प ने 5 अगस्त 2019 को राष्ट्र के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही जम्मू-कश्मीर ने शांति, सुशासन, विकास और नए अवसरों की दिशा में नई गति प्राप्त की. यह निर्णय 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक मील का पत्थर है.

अमृतसर में आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश

अमृतसर, 05 अगस्त. अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से संचालित होने वाले कथित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मॉड्यूल का पर्दाफाश करने का दावा किया है.

पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में कुल नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें चार नाबालिग भी शामिल हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से तीन अवैध पिस्तौल, चार पेट्रोल बम और नौ जिंदा कारतूस बरामद करने की जानकारी दी है. गिरफ्तार संदिग्ध कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े विदेशी संचालकों के संपर्क में थे. जांच एजेंसियों को आशंका है कि नेटवर्क का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को अपने साथ जोड़ना, संवेदनशील स्थानों की निगरानी करना और क्षेत्र में अशांति फैलाने की कोशिश करना था. जांच में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आने का दावा किया गया है. पुलिस के मुताबिक संदिग्धों ने रेलवे ट्रैक के आसपास निगरानी के लिए कैमरे लगाए थे. इन कैमरों से प्राप्त दृश्य कथित तौर पर विदेश में मौजूद संचालकों के साथ साझा किए गए. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि किन स्थानों की निगरानी की गई और यह जानकारी किस उद्देश्य से जुटाई जा रही थी. पूछताछ के दौरान कथित तौर पर यह भी सामने आया कि मॉड्यूल से जुड़े लोगों की योजना दिल्ली में आयोजित होने वाले किसी विरोध प्रदर्शन के दौरान पेट्रोल बम से हमला करने की थी. हालांकि, इस साजिश से जुड़े दावों की विस्तृत जांच अभी जारी है और पुलिस अन्य संभावित आरोपियों तथा संपर्कों की पहचान करने में जुटी है.

पश्चिम मध्य रेल
विद्युत शाखा ▪ खुली निविदा
निविदा दिनांक 01.08.2026
ई-निविदा

वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजीनियर (टीआरएस), पश्चिम मध्य रेल, नई कटनी जंक्शन, भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-निविदा आमंत्रित करता है। **निविदा सूचना क्रमांक:** एनकेजे-डीएसएल-केलिब्रेशन-टी-26, दिनांक 01.08.2026. **कार्य का नाम लोकेशन सहित: डीजल शेड, नई कटनी जंक्शन एवं विद्युत लोको शेड, नई कटनी जंक्शन के औजारों एवं परीक्षण उपकरणों के कैलीब्रेशन का कार्य। निविदा का अनुमानित मूल्य:** ₹ 4,72,420.32. **अर्नेस्ट मनी/बिड सिक्योरिटी राशि:** ₹ 9,500/-. **समापन अवधि:** 04 माह। **निविदा भरने की अंतिम तिथि एवं समय (12.00 बजे तक):** 24.08.2026. उपरोक्त ई-निविदा की संपूर्ण जानकारी वेबसाईट **http://ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। ई-निविदा के अलावा उपरोक्त कार्य के लिए कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

Kolhapur Municipal Corporation
City Water Supply & Drainage Division

E-Tender (mahatenders.gov.in) Extension 2nd

Tender Notice No.	Publish date	News Paper name	Extension No.
४१/ २०२६-२७	१५/०७/२०२६	Navbharat (H)	2

Due to no Response for the above work, date Extension is being given From Date ०५/०८/२०२६ to Date ०७/०८/२०२६.

The Terms & Conditions of Earlier Tender will be same.

अब भारत के बताए रास्ते पर चलेगा नेपाल

काठमांडू. नेपाल की सियासत में इन दिनों एक नई हलचल देखने को मिल रही है. काठमांडू के प्रधानमंत्री बालेन शाह, जो कल तक अपने तरीके से सब कुछ बदलने का दावा करते थे, अब उन्हें भी समझ आ गया है कि जमीनी विकास और गवर्नेंस का असली मॉडल तो भारत के पास ही है. बड़े-बड़े दावों और भाषणों से जब ग्राउंड पर काम करना मुश्किल होने लगा तो आखिरकार नेपाल के हुक्मरानों की अक्ल ठिकाने आई है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड | IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

सार्वजनिक सूचना
स्वर्ण नीलामी सह निमंत्रण सूचना

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (बैंक) से सोने के आभूषण गिरवी रखकर ऋण लिया था और बार-बार याद दिलाने और नोटिस भेजने के बावजूद, वे निर्धारित समय के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। तदनुसार, बैंक अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए, बकाया राशि की वसूली के लिए 08 सितम्बर 2026 से 10 सितम्बर 2026 तक गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी आयोजित करेगा। उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि निरीक्षण/बोली की तिथि से पहले लागू ब्याज, शुल्क और खर्चों सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान करने का यह अंतिम अवसर है, अन्यथा नियामक द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों को नीलामी के माध्यम से बेच दिया जाएगा।

ऋण खाता संख्या	ऋण लेने वाले का नाम	शाखा का नाम
181972623	प्रयास साहू	जबलपुर विजय नगर

नीलामी की स्थिति में यदि कोई अधिशेष राशि प्राप्त होती है, तो वह संबंधित उधारकर्ता को वापस कर दी जाएगी। नीलामी के बाद यदि कोई घाटा/कमी रह जाती है, तो शेष राशि उचित कानूनी कार्यवाही के माध्यम से उधारकर्ता से वसूल की जाएगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी खाते को नीलामी से हटाने का अधिकार रखता है। इसके अलावा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के, अपने विवेकानुसार नीलामी कार्यक्रम में संशोधन करने या उसे आगे की तिथि तक स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। नीलामी का आयोजन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के सूचीबद्ध नीलामी सेवा प्रदाताओं, मेसर्स श्रीराम ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड द्वारा सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक भौतिक रूप से किया जाएगा। यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नीलामी से संबंधित सभी शर्तें उनके नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी पर लागू होंगी।

नीलामी की शर्तें एवं नियम :
1) संबंधित सोने के आभूषणों की बिक्री "जैसा है, जहाँ है", "जैसा है, जो है" और "जो भी उपलब्ध है" के आधार पर होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को बैंक के अधिकृत नीलामी सेवा प्रदाता के साथ पंजीकरण करना होगा और केवाईसी संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
3) बोली जमा करने से पहले आभूषणों और उनकी विशिष्टताओं का निरीक्षण करना और उनसे संतुष्ट होना बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। बोलीदाता शाखा प्रबंधक से परामर्श करके आभूषणों का निरीक्षण कर सकते हैं।
4) उच्चतम बोली बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा पुष्टि के अधीन होगी।
5) सफल बोलीदाता को निर्धारित समय के भीतर पूरी बिक्री राशि जमा करनी होगी, अन्यथा जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
6) एक बार बेचे गए सोने के पाउच किसी भी परिस्थिति में विक्रेता को वापस नहीं किए जा सकते हैं और विजेता बोलीदाता/खरीददार द्वारा भौतिक रूप से सौंपे जाने के बाद विक्रेता किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
7) बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि को बिना किसी पूर्व सूचना या कारण बताए किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या नीलामी को रद्द/स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है।
8) बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है।

एसडी/-
दिनांक: 06.08.2026 **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के**
स्थान: मध्यप्रदेश **अधिकृत अधिकारी**

ICAR-National Research Centre for Grapes
Manjiri Farm, P B, No 3, Solapur Rd, Pune, Maharashtra 412308

Invitation for Bids

Tender Publication Date : 04 August 2026
Loan No. and Title : Loan 4411-IND/ Building India's Clean Plant Program
Contract No. and Title : CPC1-CW01/ Design and Build containment facility for grapes - CPC 1, Pune
Tender ID : 2026_DAREA_920526_1
Deadline for Submission of Bids : 16 September 2026

1. The Government of India has received financing from the Asian Development Bank (ADB) toward the cost of Building India's Clean Plant Program. Part of this financing will be used for payments under the Contract named above. Bidding is open to Bidders from eligible source countries of ADB.
2. The Principal Scientist (Plant Pathology), ICAR- National Research Centre for Grapes, Pune ("the Employer") invites sealed bids from eligible Bidders for the construction and completion of Design and Build containment facility for grapes – CPC 1, Pune including comprehensive Operation and Maintenance for a period of five (5) years from date of handover ("the Works")."
3. Open competitive bidding will be conducted in accordance with ADB's Single-Stage: Two-Envelope bidding procedure and is open to all Bidders from eligible countries as described in the Bidding Document.
4. Only eligible Bidders with the following key qualifications defined in the Bidding Document may participate in this bidding:
   - Minimum average annual turnover of **INR 507 million (USD 5.33 M)** within the last three (3) years;
   - Participation as a contractor, JV partner, or Subcontractor in **at least one (1) contract ≥ INR 304 million (USD 3.2 M), OR at least two (2) contracts each ≥ INR 190 million (USD 2.0 M),** satisfactorily completed within the last five (5) years;
   - Participation in at least one (1) contract for design and construction of a controlled-environment plant containment/quarantine facility ≥ 400 sqm, operational within the last ten (10) years.

   For the complete eligibility and qualification requirements, Bidders should refer to the Bidding Document.
5. To obtain further information and inspect the bidding documents, Bidders should contact:
   The Principal Scientist (Plant Pathology)
   ICAR-National Research Centre For Grapes,
   P.B. No. 3, P.O. Manjari Farm, Solapur Road,
   Pune-412307, Maharashtra, India
   Telephone 020 2695 6000
   Web: https://nrcgrapes.icar.gov.in/
   Email: sujoyta@gmail.com
6. To purchase the Bidding Document in English, eligible Bidders should
   - register and download the bidding documents from Employer's procurement portal **https://eprocure.gov.in/eprocure/app**
   - The Employer shall not be held liable for any information not received by the Bidder, and it is the Bidder's responsibility to regularly check the website for the latest information related to this invitation for bids.
   - The Bidding Documents are available for free download from the Employer's e-procurement portal. No fee is payable.
7. Deliver your bid
   - Bidders shall submit their Bids electronically only through the public procurement website **https://eprocure.gov.in/eprocure/app** on or before the deadline: Date: 16 September 2026 Time: 11:00 hours (IST)
   - together with a Bid Security as described in the Bidding Document

   Technical Bids will be opened publicly online on: Date: 16 September 2026, Time: 11:15 hours (IST), via the e-procurement portal https://eprocure.gov.in/eprocure/app and at: ICAR-National Research Centre for Grapes, P.B. No. 3, P.O. Manjari Farm, Solapur Road, Pune - 412307. Price Bids will be opened at a date and time to be notified to qualifying bidders following Technical Bid evaluation.
8. This Invitation for Bid is also published on the following websites
   https://eprocure.gov.in/eprocure/app
   https://nhb.gov.in/
   https://www.nrcgrapes.in/
   https://www.adb.org/projects/57041-001/main

s/d
Administrative Officer